(iii) <u>सार्वजनिक ऋण</u> — सार्वजनिक ऋणों का उपयोग भी मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन की स्थिति को दूर करने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक ऋण के अन्तर्गत सरकार जो जनता से उधार लेती है और उसका जो भुगतान करती है दोनों सम्मिलित हैं। सरकार जब जनता से उधार लेती है तो उसका प्रभाव करारोपण के समान होता है क्योंकि इसके द्वारा जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति सरकार के पास उधार के रूप में आ जाती है। इसी प्रकार जब सरकार सार्वजनिक ऋण का भुगतान करती है तो उसका प्रभाव सार्वजनिक व्यय के समान पड़ता है क्योंकि उससे व्यक्तियों के पास मूलधन और ब्याज के रूप में अतिरिक्त क्रय शक्ति आ जाती है और प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होती है।

यद्यपि विभिन्न प्रशुल्क यन्त्रों के समुचित प्रयोग से हम आर्थिक स्थायित्व की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं परन्तु इस नीति की भी कुछ समस्याएँ हैं जो निम्न हैं (i) सार्वजनिक व्यय में आये दिन और सहसा परिवर्तन करना आसान नहीं है। (ii) सरकारी योजनाएँ भी जल्दी जल्दी नहीं बदली जा सकतीं (iii) कर प्रणाली में आये दिन आकस्मिक परिवर्तन करना आसान नहीं है (iv) प्रशुल्क नीति दुधारी तलवार की भाँति है। यदि थोड़ी सी भी सरकारी व्यय की दिशा में गलती हुई तो या तो स्फीति हो जायगी या मन्दी आ जायगी।

(2) मौद्रिक नीति — मौद्रिक नीति से आशय आर्थिक स्थिति में वांछित परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन है। दूसरे शब्दों में, मौद्रिक नीति के अन्तर्गत वे सभी उपाय आ जाते हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण के उपकरणों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। मौद्रिक नीति मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति को रोकने में सहायक होती है। केन्द्रीय बैंक जिन तरीकों से साख का नियंत्रण करता है उन्हें साख नियंत्रण उपकरण कहते हैं इन उपकरणों को हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे।

(i) बैंक दर नीति — बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है। यदि बैंक दर में वृद्धि की जाती है तब व्यापारिक बैंक भी अपने ऋणों की ब्याज दरों में वृद्धि करने के लिए विवश हो जाते हैं। स्फीति को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक दर में वृद्धि कर देनी चाहिए बैंक दर में वृद्धि हो जाने से व्यवसायी एवं उपभोक्ता बैंकों से अधिक ऋण लेना पसन्द नहीं करते जिससे अर्थव्यवस्था के स्फीतिक दबावों की तीव्रता में गिरावट आ जाती है। उसके विपरीत अर्थव्यवस्था को मन्दी से ऊपर उठाने के लिए केन्द्रीय बैंक को बैंक दर घटा देनी चाहिए ताकि ऋण सस्ता हो जाय और ऋणों पर आधारित व्यवसायों को प्रोत्साहन मिले।

(ii) खुले बाजार की क्रियाएँ — स्फीति को रोकने के लिए उपयुक्त नीति यह है कि केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचे। प्रतिभूतियों के विक्रय के फलस्वरूप साधारणतया व्यापारिक बैंक की जमा में कमी आ जाती है। व्यापारिक बैंकों की जमा में कमी होने से उनकी उधार देने की क्षमता कम हो जाती है और बैंक ऋण घट जाते हैं उसके विपरीत मन्दी काल में केन्द्रीय बैंक को प्रतिभूतियों को खरीदना चाहिए ताकि व्यापारिक बैंकों के पास नकद जमा की मात्रा बढ़ जाय और उनकी उधार लेने की क्षमता में वृद्धि हो तथा साख का विस्तार हो।

(3) प्रासंगिक अनुपातों में परिवर्तन — जब देश में मुद्रा प्रसार हो तो केन्द्रीय बैंक को प्रासंगिक अनुपात को बढ़ा देना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि केन्द्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों द्वारा रखा जाने वाला अनुपात 20% से बढ़कर 25% कर दिया जाता है तो व्यापारिक बैंक को केन्द्रीय बैंक के पास अधिक धन राशि जमा करनी पड़ेगी इसलिए इसी अनुपात में व्यापारिक बैंकों की अपने ग्राहकों को ऋण देने की शक्ति सीमित हो जायगी। फलतः मुद्रा प्रसार की तीव्रता कम हो जायगी।

(4) मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन — मार्जिन की ऊँची दर मौद्रिक प्रसार को रोकने में समर्थ होती है। केन्द्रीय बैंक को लिए उपयुक्त नीति यह है कि तेजी काल में मार्जिन की आवश्यकताओं को बढ़ा दे और मन्दी काल में मार्जिन की आवश्यकता को घटा दें।

(2) उपभोक्ता का साख नियंत्रण — स्फीति काल में केन्द्रीय बैंक को उपभोक्ता साख, संकुचन के लिए अधिकांश उपभोग वस्तुओं पर उपभोक्ता साख नियंत्रण नियम लागू करना चाहिए (i) विशिष्ट वस्तु की पहली किस्त की राशि अधिक रखनी चाहिए (ii) भुगतान काल की अवधि को कम कर देना चाहिए। मन्दी काल में उपभोक्ता साख के विस्तार के लिए अवशर्तों को ढीला कर देना चाहिए।

किन्तु मौद्रिक उपायों की एक सीमा होती है (i) अकेले मौद्रिक उपचार ही मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन पर रोक लगाने हेतु सफल प्रमाणित नहीं हुए हैं (ii) वास्तविक विनियोगकर्ताओं पर अंकुश रखने के लिए सरकारें असमर्थ रहती हैं (iii) मौद्रिक नीति प्रायः इतनी कोमलता से लागू की जाती है कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं के बराबर होती है। प्रो० हॉम का कहना है कि अकेली मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता नहीं ला सकती है। इसी प्रकार रैडक्लिफ समिति का विचार है कि स्फीति काल से मौद्रिक नीति प्रभावशाली हो सकती है परन्तु मन्दी काल में इसकी क्षमता अत्यंत सीमित है।

③ भौतिक नियंत्रण — प्रो० फीशर ने कीमत नियंत्रण को स्फीति का मुकाबला करने के लिए एक उत्तम साधन माना है। कीमत नियंत्रण के अन्तर्गत अधिकतम सीमा निश्चित की जाती है जिससे अधिकतम कीमतें स्फीति काल में नहीं बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत कीमत स्थैर्य के अन्तर्गत कम से कम सीमा निर्धारित की जाती है जिससे कम कीमतें मन्दी में नहीं गिरती। ज्यों ही कीमतें इन सीमाओं को पार करती हैं सरकार स्फीति काल में कीमत नियंत्रण के साथ साथ राशनिंग व्यवस्था लागू करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करती है। इसके विपरीत मन्दीकाल में ज्यों ही कीमतें गिरती हैं सरकार खुले बाजार में भारी स्टाक खरीदकर उत्पादकों की रक्षा करती है, परन्तु इन नीतियों की सफलता के लिए भारी साधन, उचित समय तथा कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता होती है।

अन्य उपाय — ऊपर वर्णित उपायों के अतिरिक्त कुछ और भी उपाय हैं जिससे व्यापार चक्र को नियंत्रण में किया जा सकता है। ये उपाय निम्नलिखित हैं।

① औसत कुल लागत व औसत मूल्य स्तर में समानता — यह भी सुझाव दिया जाता है कि तेजी रोकने के लिए औसत कुल लागत व औसत मूल्य स्तर को समान रखा जाय जिससे न तो लाभ होगा, न हानि और फलतः अभिवृद्धि समाप्त हो जायगी। परन्तु इसको कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं।

Scanned with CamScanner